ग्लोबलाइजेशन के संबंध में फिक्की की रिपोर्ट

*168. डा. मुरली मनोहर जोशी : ††

श्री राम जेठमलानी :

क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंड्स्ट्रीज की फेयर ग्लोबलाइजेशन नामक अध्ययन रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि इस रिपोर्ट में भारत की अर्थव्यवस्था को अमरीका तथा जापान की अर्थव्यवस्था की तुलना में अधिक उदार बताया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) जी, हां ।

(ख) और (ग) रिपोर्ट के अनुसार, यह कहा गया है कि भारत अब विश्व की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं – संयुक्त राज्य अमरीका और जापान की अपेक्षा अधिक खुली अर्थव्यवस्था है । यह दावा सकल घरेलू उत्पाद (जी डी पी) के एक अनुपात के रूप में पण्य वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात और आयात के हिस्से पर आधारित है । कोई आवश्यक नहीं है कि ऐसे अनुपात से अर्थव्यवस्था के उदारीकरण की स्थिति प्रदर्शित हो ।

भारत समग्र आर्थिक सुधार के हिस्से के रूप में क्रमिक और अंशाकिंत ढ़ंग से अर्थव्यवस्था को खोलने की नीति का अनुसरण कर रहा है । यह कार्य घरेलू पणधारकों के हित की रक्षा करते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रतिस्पर्धी शाक्ति को बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है । भारत की औसत और सर्वाधिक शुल्क दरों को सुसंगत ढंग से कम किया गया है । तथापि, अमरीका और जापान सहित अधिकांश विकसित देशों में औसत शुल्क दरें भारत की दरों से कम है ।

FICCI report on Globalisation

†168. DR. MURLI MANOHAR JOSHI: ††

SHRI RAM JETHMALANI:

Will the Minister of COMMERCE AND INDUSTRY be pleased to state:

†Original notice of the question was received in Hindi.

††The question was actually asked on the floor of the house by Dr. Murii Manohar Joshi.

(a) whether Government's attention has been drawn to the study report namely "Fair Globalisation" of the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industries;

(b) if so, whether it is a fact that the Indian economy has been reported to be more liberal than that of the economy of US and Japan; and

(c) if so, Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI KAMAL NATH):

(a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Yes, Sir.

(b) and (c) According to the Report it has been stated that India is now a more open economy than the world's two largest economies—the United States and Japan. This assertion has been based on share of merchandise and services exports and imports as a ratio of GDR Such a ratio does not necessarily reflect the state of liberalisation of the economy.

India has been following the policy of opening up the economy in a gradual and calibrated manner as part of the overall economic reform process. This is done with the aim of enhancing the competitiveness of the Indian economy while at the same time protecting the interest of the domestic stake holders. India's average and peak rates of duty have been reduced consistently. The average duty rates in most developed countries, including the USA and Japan, are however, lower than that of India.

डा. मुरली मनोहर जोशी : सभापति जी, इस वक्तव्य से जो यहां रखा हुआ है, मेरे प्रश्न का स्पष्ट उत्तर नहीं आता है । फिर भी, इन्होंने यह स्वीकार किया है कि जिस रिपोर्ट का मैंने हवाला दिया था, उसके अनुसार तो जापान की और अमेरिका की अपेक्षा भारत की अर्थव्यवस्था अधिक लिबरलाइज्ड है, अधिक उदारीकत है । लेकिन वे यह कहते है कि यह कोई आवश्यक नहीं है कि जो अनुपात उसमें बतायें गये है, वे हमारी उदारीकरण की असली हालत को बताते ही हों । इसलिए मेरा मंत्री महोदय से सवाल है कि एक तो सदन को यह बतायें कि आपकी निगाह में, सरकार की निगाह में उदारीकरण की स्थिति, स्टेट्स किन indices पर, किन फैक्टर्स पर निर्भर करती है कि आप कहेंगे, ये हो गये, तो उदारीकरण हो गया ? भारत की अर्थव्यवस्था आपकी निगाह में किस

हद तक उदारीकृत हुई है और क्या आप इसे पूरी उदारीकृत करने के लिए कुछ और कदम उठायेंगे ? अगर आप और कदम उठायेंगें, तो क्या सरकार में और आपके सहयोगी दलों में, उस पर कोई सहमति हुई है ?

श्री कमल नाथ : सभापति महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न बड़ा लम्बा है । सर, जो प्रश्न आदरणीय सदस्य का था, इसमें उदारीकरण का जहां तक विषय है, इसकी डेफिनेशन क्या है, जो फिक्की की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि हमारी इकानामी यू.एस. और जापान से ज्यादा लिबरलाइज्ड है । सर उन्होंने उस आधार पर कहा है कि जो हमारा ट्रेड और जीडीपी का रेश्यो है । आज ग्लोबल लिबरलाइलेशन के मूल्यांकन करने का जो तरीका है, वह यह है कि जीडीपी और ट्रेड का क्या रेश्यो है । यूनाइटेड स्टेट का जीडीपी इतना बड़ा है, तो आवश्यक है कि वह इंडिया के बाद आयेंगे । हमारा ट्रेड ज्यादा है जीडीपी कम है, तो यह एक ही डेफिनेशन है, एक ही मापदंड इसका है । जहां तक यह कहना कि हम उस सीमा तक पहुंच गये है, that we have exceeded now our limits of liberalisation and globalisation.... *(Interruptions)*...

डा. मुरली मनोहर जोशी : सभापति महोदय, मेरा मंत्री जी से सीधा सवाल है कि आपकी निगाह में और सरकार की निगाह में वे कौन से पैरामीटर्स है, कौन से indices है जिनके आधार पर आप कहेंगे कि अब अर्थव्यवस्था पूर्णत : उदारीकृत है ?

श्री कमल नाथ : सर, इसमें जो हमारे इकनामिक ग्रोथ इंडीकेंटर्स है । इकनामिक ग्रोथ इंडीकेटर्स जीडीपी ग्रोथ होता है, हमारे मैन्युफैक्चरिंग सैक्टर का ग्रोथ रेट होता है, हमारा ग्रोथ रेट होता है और इसके साथ-साथ हमारा एम्पलायमेंट जेनरेशन का ग्रोथ रेट होता है । वर्ष 1991 से लेकर 2003 तक हमारा जो एम्पलायेमेंट जेनरेशन था, वह घटा था । यह स्पष्ट आंकड़े बताते है कि वर्ष 1981 से लेकर 1991 तक हमारी एम्पलायमेंट जेनरेशन लगभग तीन प्रतिशत थी और वर्ष 1991 से 2003 तक हमारी एम्पलायमेंट जेनरेशल 1.1 तक आई । आज हमारी गवर्नमेंट का सबसे बड़ा लक्ष्य एम्पलायमेंट जेनरेशन का है । मैं तो यह मानता हूं कि कोई भी मापदंड आज अपने देश में सबसे ज्यादा आवश्यकता किसी भी अर्थव्यवस्था को नापने का तरीका कवेल एम्पलायमेंट जेनरेशन होना चाहिये और यही तरीका आपनी सरकार का है । जहां तक माननीय सदस्य का प्रश्न है, तो हमारे आपसी तालमेल के संबंध में है, तो हमारे गठबंधन की पार्टियों में पूरा तालमेंल है ।

श्री मुरली मनोहर जोशी : सभापति महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं । मैंने जो सवाल पूछा था, मंत्री जी उसके इधर-उधर घूम रहे है । मेरा स्पष्ट प्रश्न यह था कि भारत सरकार की निगाह में पूर्ण उदारीकरण की प्रक्रिया हो गयी, यह कब माना जाये और वे पूर्ण उदारीकरण के लिए क्या उपाय अपना रहे है ? इसका जवाब नहीं आया है ।

श्री कमल नाथ : सभापति महोदय, माननीय सदस्य को आपके संरक्षण की आवश्यकता नहीं है । मैं उन्हें पूरी तरह से तसल्ली दे दूंगा । सर, यह एक कंटीन्युइंग प्रोसेस है । यह रास्ता बहुत लम्बा है । क्योंकि हम कोई भी आंकड़े लें, कंजम्पशन फिगर्स लें, पर-केपिटा कंजम्पशन लें, अभी तक इसमें बहुत समय है ।

श्री सभापति : ठीक है; ठीक है । श्री नीलोत्पल बसु ।

डा. मुरली मनोहर जोशी : सर, अभी तो मेरा...।

श्री सभापति : आप बैठ जाइये ।

डा. मुरली मनोहर जोशी : सर, मेरा सेंकेंड सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है । ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : आपके दोनों प्रश्न हो गये । आपके तीन प्रश्न हो गये । आप दो की बात करेंगे, तो आपके तीन प्रश्न हो गये । ...(**व्यवधान**)... ।

डा. मुरली मनोहर जोशी : सर, तीन प्रश्न नहीं हुये है । मैंने तो...(**व्यवधान**)... ।

श्री सभापति । आप चौथा प्रश्न कर रहे है । आप बैठ जाइये । ...(**व्यवधान**)...

डा. मुरली मनोहर जोशी : सर, मैंने तो एक ही प्रश्न किया है ।

श्री सभापति : नहीं, नहीं , । आप बैठ जाइये । आपने बर्बाद कर दिया ...(**व्यवधान**)...

श्री दीपांकर मुखर्जी : तालमेल की बात पूछ ली । ...(**व्यवधान**)...

डा. मुरली मनोहर जोशी : वह तो पूरा एक ही सवाल था । ...(**व्यवधान**)...

श्री दीपांकर मुखर्जी : अगर तालमेल का प्रश्न नहीं आता तो दूसरा सप्लामेंटरी भी हो जाता आप तालमेल ले आए ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : जोशी जी आपके दो प्रश्न हो गये है । ...(**व्यवधान**)... आपके दो क्वेश्चन हो गये थे । ...(**व्यवधान**)...

डा. मुरली मनोहर जोशी : श्रीमान् वह पहला सवाल था । उसका उत्तर नहीं दिया था । ...(**व्यवधान**)... वह एक ही सवाल था जिसका मंत्री जी ने उत्तर नहीं दिया था । ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : उत्तर नहीं दिया तो मैं क्या करूं ? क्वेश्चन तो दो बार कर लिया आपने । ...(**व्यवधान**)...

डा. मुरली मनोहर जोशी : इसलिए मैं दूसरा सवाल पूछ रहा हूं ।

श्री सभापति : अब बोलने दीजिए इनको ।

डा. मुरली मनोहर जोशी : महोदय, बहुत आसान-सा सवाल है ।

श्री सभापति : ठीक है, पूछिए । बसु जी, आप एक मिनट बैठ जाइए । ...(**व्यवधान**)... आप एक मिनट इनको बोलने दीजिए ।

डा. मुरली मनोहर जोशी : श्रीमान्, कृषि क्षेत्र में उदारीकरण किए जाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में बहुत से दबाव हमारे ऊपर आ रहे है । मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि कृषि क्षेत्र में जो अनुदान हम दे रहे है, उसको बचाए रखने के लिए और जो पश्चिमी देश चार सौ बिलियन डॉलर प्रति वर्ष का कृषि क्षेत्र को अनुदान दे रहे है, उसको बंद कराने के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी ?

श्री कमल नाथ : सर, जो हमारा अनुदान है, वह सुरक्षित रहेगा । यह स्टैंड डब्ल्यूटीओं में अभी जुलाई महीने में हमने लिया है इसमें कोई शक नहीं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, वे 1 बिलियन डॉलर पर डे अनुदान अपने कृषि क्षेत्र को देते है और हमारा 1 डॉलर पर महीना है । इस प्रकार 1 बिलियन पर डेवर्सिज़ 1 डॉलर पर मंथ है । यह स्वीकार किया गया है कि जो हमारा अनुदान है, वह उस क्षेत्र में आता है जो सुरक्षित रहेगा ।

डा. मुरली मनोहर जोशी : उसको बंद कराने के लिए आप क्या कर रहे है ?

श्री सभापति : अब चौथा नहीं होगा ।

SHRI NILOTPAL BASU: Sir, there is some confusion in the answer. What the hon. Commerce Minsiter was trying to say would have been acceptable had the last sentence of the statement not been there. The statement says, "the average duty rates of most developed countries, including the USA and Japan are, however, lower than that of India."

Now, it is implied in the reply that the average duty imposed by countries is an indicator of the degree of liberalisation. Sir duties are imposed by countries and they are essentially functions of the comparative strengths or weaknesses of economies. If an economy is very strong, they can afford to lower the duty and, at the same time, have advantage in terms of trade exchanges. As the Commerce Minister has himself stated.....

MR. CHAIRMAN: Please, put your question.

SHRI NILOTPAL BASU: Yes, Sir.

The hon. Minister was talking about 'one billion dollar per day' and 'one billion dollar per month'. So, even if they reduce, they appear to be liberalising, and yet they remain far less liberalised in the context of the relative strengths

of our economy. So, I wish to know whether it is correct to say or imply that average duties of countries are indicators of liberalisation.

SHRI KAMAL NATH: Sir, I draw the attention of the hon. Member to the first part of my answer. The first part of my reply to this question relates to the FICCI report, and how the FICCI report has measured the globalisation.

Sir, one of the methods by which the openness of economy is determined is by the ratio between GDP and trade. And what is trade? Trade is imports and exports. If our duties are high, our trade will be less. So, as a ratio of GDP, if GDP is higher, our trade is lower, obviously it will be a different ratio.

Sir, we rank 118 amongst 122 countries in our tariffs. And that is the point I was trying to make that though we have had a gradual calibration of duties towards the reducation side, this has led to higher trade and countries reciprocate. It is very important to note that even as we are reducing our tariffs, countries to which we are exporting are also reducing their tariffs. So, while it gives an opportunity for us to export, also imports become easier, imports become more accessible to the Indian industry, and that leads to higher trade. Higher trade, then, as a measure, as a percentage of GDP, gives a different picture when it is in the context of lower tariffs.

SHRI NILOTPAL BASU: But not at the cost of the Indian industry.

SHRI KAMAL NATH: Obviously not, Sir. Not at the cost of the Indian industry.

Admission guidelines in KVS

*169. SHRI JANESHWAR MISHRA: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the details of the guidelines issued by the KVS governing admission in the Kendriya Vidyalayas;

(b) whether these guidelines have been approved by Government;

(c) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor;

(d) the criteria or deadline fixed for calculation whether adequate eligible children are available or not for admission in a particular KV in Class 11th, stream-wise; and